बृहस्पतिवार
34 साल से देहरादून का विश्वास
12 फरवरी 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 20
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

पत्थरों से कुचलकर युवक-युवती की हत्या

हमारे संवाददाता

नैनीताल। देवभूमि में कानून व्यवस्था कितनी लचर व लाचार हो चुकी है इसकी बानगी हर रोज दिखायी दे रही है। बीते रोज राजधानी देहरादून में बदमाशो द्वारा एक व्यवसाई की हत्या दिन दहाड़े कर दिये जाने के बाद हल्द्वानी से भी एक सनसनीखेज खबर सामने आयी है। यहां मंडी परिसर के भीतर बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा एक युवक और युवती की पत्थरों से कूच कर हत्या कर दी गयी। घटना की जानकारी तब मिली जब श्रमिक वहां पहुंचे और उन्होने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार युवती की उम्र करीब 20 से 22 साल और युवक की लगभग 25 साल बताई जा रही है। युवक की जेब से अल्मोड़ा जिले की एक आईडी बरामद हुई है, जिसके आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि की कोशिश की जा रही है। वहीं युवती की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। घटनास्थल की स्थिति देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि दोनों की हत्या देर रात की गई। हत्या में बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो मौके पर ही पड़े मिले। युवक की जेब से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हालांकि पुलिस इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित कुमार और कोतवाल विजय मेहता सहित भारी पुलिस बल पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण जा रहा है आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। बुरी तरह से दोनों के मुंह कुचले हुए हैं, जिस कारण शिनाख्त में दिक्कत आ रही है।

अर्जुन शर्मा हत्याकाण्डः मुठभेड के बाद हत्यारोपी दो सगे भाई गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। अर्जुन शर्मा हत्याकाण्ड के मामले में पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दो हत्यारोपी सगे भाई निकले। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस परेड ग्राउंड के सामने जीएमएस रोड निवासी गैस एजेंसी स्वामी अर्जुन शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। हत्याकाण्ड के बाद शहर में लोगों में काफी दहशत का माहौल पैदा हो गया था। लोगों ने पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिये थे। आज प्रातः पुलिस की नाकेबन्दी के चलते पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने दो बदमाशों को अलग-अलग क्षेत्रों में चैकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनो बदमाशों के मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। जिनका उपचार जारी है।

जानकारी के अनुसार बीती रात रायपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया हुआ था।

इस दौरान लाडपुर के जंगल में एक बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गयी पुलिस ने मुठभेड में उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड में बदमाश के पैर में गोली लग गयी जिसको गिरफ्तार कर कोरोनेशन अस्पताल में ले जाया गया। वहीं चैकिंग के दौरान स्कूटी सवार एक बदमाश द्वारा लालतप्पड पुलिस चौकी पर पुलिस के रोकने पर न रूककर वापस पीछे भागकर खंडहर फैक्ट्री में घुसकर पुलिस पार्टी पर फायर किया गया जवाबी कार्यवाही में मुठभेड में एक बदमाश को गिरफ्तार किया।

मुठभेड में गिरफ्तार बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो देशी तमंचे बरामद किये। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम पंकज राणा पुत्र अभय राम सिंह व राजीव उर्फ राजू पुत्र अभय राम सिंह निवासी 61/3 इंदरा कॉलोनी चक्खुवाला कोतवाली देहरादून बताया।

दोनों बदमाशों ने अपने पिता की भी की थी हत्या

देहरादून। अर्जुन शर्मा हत्याकाण्ड में पकडे गये दोनों बदमाश राजू व पंकज चुक्खुवाला इन्द्रा कालोनी के निवासी हैं। दोनों ने क्लेमनटाउन स्थित एक शिक्षण संस्थान में काम करने वाले अपने पिता अभय राम सिंह की भी लगभग दस साल पहले गला घोंटने के बाद गोली मारकर हत्या की थी। उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि देखने में काफी शांत स्वभाव के लगने वाले दोनों भाई अन्दर से काफी शातिर किस्म के निकलेंगे यह मौहल्ले वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा है।

दून वैली मेल

संपादकीय

क्या बन सकेगा उत्तराखण्ड नशा मुक्त राज्य?

बीते रोज उत्तराखण्ड की कैबिनेट की बैठक में राज्य को नशा मुक्त किये जाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए एक प्रस्ताव को पारित कर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के स्थायी ढांचे को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही इसमें 22 पदों के सृजन किये जाने को मंजूरी दे दी गयी है। सोचनीय सवाल यह है कि क्या सिर्फ कार्यालयों में बैठ कर राज्य को नशा मुक्त किया जा सकता है? उत्तराखण्ड राज्य इन दिनों नशे की पूरी तरह गिरफ्त में आ चुका है। जबकि राज्य की सरकारें पिछले 12-15 वर्षो से राज्य को नशा मुक्त राज्य बनाने का दावा करती रही है। अब तो पुलिस प्रशासन की ओर से जब भी मीडिया को किसी भी नशा तस्करों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी जाती है तो उस प्रेस विज्ञप्ति में भी यह दावा किया जाता है कि राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा यह कार्य किया गया है। क्या राज्य को नशा मुक्त बनाने का सिर्फ यही तरीका है। जबकि उत्तराखण्ड के निवासी यह तक जानते है कि यहां राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भांग की खेती कर चरस बनायी जाती है तो वहीं यूपी के बरेली सहित अन्य जिलों से स्मैक व हेरोइन की तस्करी कर उत्तराखण्ड पहुंचायी जाती है। जब यह बात आम नागरिको को पता है तो क्या यह बात शासन प्रशासन को नही पता है, यह सोचनीय सवाल है? जबकि शासन प्रशासन यह सब जानते हुए भी मौन है। शासन-प्रशासन को अब यह सोचना होगा कि राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए उसे धरातल पर कार्यवाही करने की जरूरत है नहीं तो सिर्फ कागजो व कार्यालयों में बैठ कर राज्य को कभी भी नशामुक्त राज्य नहीं बनाया जा सकेगा।

सरकारी जमीन को मुस्लिम संस्था को आवंटन करने के विरोध में किया प्रदर्शन

संवाददाता

देहरादून। आईएमए के समीप जमीयत उलेमा-ए-हिन्द को सरकारी जमीन आवंटित किये जाने के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिलाअधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया।

आज यहां विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के प्रांतीय मिलन प्रमुख विकास वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए। जहां पर उन्होंने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य अकादमी के समीपवर्ती क्षेत्र में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द नामक संस्था को सरकारी भूमि आवंटित किये जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है वह अत्यंत गम्भीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडा विषय है। जमीनयत उल्लेमा-ए-हिन्द स्वयं को शैक्षाणिक उद्देश्य से 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी' की स्थापना हेतु भूमि आवंटन का इच्छुक बताती है किन्तु देशभर में इस संस्था की वैचारिक पृष्ठभूमि, पूर्व गतिविधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे जुडी संस्थाओं को लेकर अनेक बार कटटरपंथी और देश विरोधी विचारधाराओं से सम्बन्ध होने की आशंकाएं व्यक्त की जाती रही है। यह विशेष रूप से चिन्ताजनक है कि प्रस्तावित भूमि भारतीय सैन्य अकादमी जैसे अत्यंत संवेदनशील सैन्य संस्थान के निकट स्थित है। इस प्रकार के क्षेत्र में किसी भी ऐसी संस्था की स्थापना, जिसकी विचारधारा या गतिविधियों को लेकर संदेश की स्थिति हो, सेना की सुरक्षा, खुफिया तंत्र तथा राष्ट्रीय हितों के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। इसे सेना के सुरक्षा तंत्र के समीप सम्भावित जोखिम तत्वों को प्रवेश देने के समान माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी भूमि को ऐसी मुस्लिम कटटर विचारधारा मौहम्मद असद मदनी की संस्था को देना उत्तराखण्ड में अवैध मुस्लिम घुसपैठ को बढावा देने और उत्तराखण्ड की डेमोक्रेसी को चेंज करने का षडयंत्र दिखायी दे रहा है। उत्तराखण्ड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माध्यम से देवबंद जैसी हिन्दू विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों का बडा केन्द्र स्थापित करने का षडयंत्र था जिसे बजरंग दल किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। देश की सुरक्षा एजेंसियो की सुरक्षा और उत्तराखण्ड की डेमोक्रेसी के साथ कोई खिलवाड नहीं होने दिया जायेगा। प्रदर्शन करने वालों में अशीष बलूनी, मनोज पाल, राघव उपाध्याय, आशीष शर्मा, सौरभ गौतम, सचिन चौधरी, अर्पण, सन्नी, गोविन्द, राशिराम वर्मा, अशोक वर्मा, विरेन्द्र शर्मा, राजेश सोमवंशी, अमित गुप्ता, मुकेश शर्मा, चन्द्रप्रताप, यशवधन मौर्य, हर्ष सहगल, नरेश शर्मा, हितेश शर्मा, अमन राजवंशी, गगन चौधरी, दर्पण चौधरी, ध्रुव चौधरी, हरीश कोहली आदि शामिल रहे।

राष्ट्रीय साइक्लिंग चैंपियनशिप 2026 में उत्तराखंड का दमदार आगाज

संवाददाता

अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय साईक्लिंग चैपियनशिप में उत्तराखण्ड ने दमदार आगाज करते हुए अनुशासन व आत्मविश्वास के साथ अपनी भागीदार दर्ज करायी। आज यहां पूर्वोत्तर भारत की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से सजी रोइंग की धरती पर आयोजित 'राष्ट्रीय साइक्लिंग चैंपियनशिप 2026' में उत्तराखंड की टीम ने पूरे जोश, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी भागीदारी दर्ज कराई। यह प्रतियोगिता 12 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसका आयोजन 'साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा किया गया है। हरे-भरे पहाड़, स्वच्छ वातावरण और सरल, मेहनती व मधुर स्वभाव के स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी के बीच उत्तराखंड की टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। रोइंग की प्राकृतिक वादियाँ खिलाड़ियों के लिए किसी प्रेरणा स्थल से कम नहीं रहीं। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड से कुल 19 खिलाड़ी (4 बालिकाएँ और 15 बालक) विभिन्न आयु वर्ग और इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। टीम में 'एलीट, 23 वर्ग, जूनियर, सब-जूनियर और यूथ' वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं।

समिति ने किया तेल व गैस परखवाडे के तहत गोष्ठी का आयोजन

संवाददाता

देहरादून। आज यहां नेताजी संघर्ष समिति के कार्यालय कांवली रोड पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। तेल और गैस बचत पखवाडा के तहत गोष्ठी की अध्यक्षता समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात डंडरियाल और संचालन समिति के प्रमुख महासचिव आरिफ वारसी ने किया। गोष्ठी में विशेष आमंत्रित राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती थे। गोष्ठी में प्रवक्ताओं ने गैस और तेल बचत करने पर विशेष जोर दिया। प्रदीप कुकरेती और प्रभात डंडरियाल ने कहा कि अगर आज हम तेल की बचत नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमें पैदल चलना होगा समय की मांग है कि हम तेल बचाएं। आरिफ वारसी और विपुल नौटियाल ने कहा कि हमें गैस आवश्यकता अनुसार जलानी चाहिए। प्राय देखा गया है कि लोग बातों में लगकर गैस खुली छोड़ देते हैं जिससे गैस भी ज्यादा लगती है और कभी-कभी हादसा होने की संभावना हो जाती है। इस गोष्ठी में आरिफ वारसी, प्रभात डंडरियाल, दानिश नूर, प्रदीप कुकरेती, विपुल नौटियाल, सुशील विरमानी, पारस यादव, जय बिष्ट, विनोद असवाल ,इम्तियाज अहमद, संदीप गुप्ता ,गुलाम मुस्तफा, इलियास कुरैशी सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने की मांग

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का जीवन और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय/वन्यजीव संरक्षण नीति तत्काल लागू करने की मांग करते हुए वन विभाग के अधिकारियों को भेजा मांग पत्र।

संयुक्त नागरिक संगठन की ओर से भेजे गए ज्ञापन में जंगली जानवरों का जीवन और मानव-वन्यजीव संघर्ष मुख्य रूप से पशु पक्षियों के निवास स्थान के विनाश,अवैध शिकार,जलवायु परिवर्तन, जंगलों में आग और भोजन की कमी को संघर्ष का मुख्य कारण बताते हुए लिखे पत्र में बताया गया है की जंगली जानवरों के निवास स्थान का विनाश (हैबिटेट लॉस),विकासात्मक परियोजनाओं,सड़कों और शहरीकरण के कारण जंगलों का दायरा सिमट रहा है,जिससे वे बस्तियों की ओर आने को मजबूर हैं।जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज)तापमान में वृद्धि के कारण, गुलदार और भालू जैसे जानवर सर्दियों में हाइबरनेशन (शीतनिद्रा) नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी गतिविधि बढ़ जाती है। सूखे और बारिश में अनियमितता से जंगल में भोजन की कमी हो रही है,जिससे वे गांवों की ओर आ रहे हैं। हर साल लगने वाली जंगल की आग से वन्यजीवों का आवास और भोजन नष्ट हो रहा है। राज्य में तेंदुए जैसे जानवरों का खाल और अंगों के लिए अवैध शिकार किया जा रहा है। भोजन की कमी के कारण जानवर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं,जहाँ वे मवेशियों और इंसानों को शिकार बना रहे हैं। समस्या के स्थाई समाधान हेतु वन्यजीव संरक्षण हेतु ठोस नीति बनाई जाने की इस मांग करने वालों में जगमोहन मेहंदीरता, प्रदीप कुकरेती, सुशील त्यागी, नवीन सदाना,मुकेश शर्मा आदि जागरूक लोगों शामिल थे।

किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

संवाददाता

देहरादून। राजकीय इंटर कालेज पटेलनगर में किशोरावस्था एवं इस दौरान होने वाली परेशानियों व परिर्तन विषय पर जागरूक कार्यक्रम का आयोजन।

आज यहां राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी), पटेल नगर में 'किशोरावस्था एवं इस दौरान होने वाली परेशानियाँ और परिवर्तन' विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलावों और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना था। राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान से आई मुख्य वक्ता और साइकेट्रिक सोशल वर्कर बीना रावत ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किशोरावस्था जीवन का एक अत्यंत संवेदनशील चरण है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिन्हें समझना प्रत्येक किशोर के लिए आवश्यक है। रावत ने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए बताया कि वर्तमान समय में किशोरों में चिड़चिड़ापन, उदासी, तनाव और अनिद्रा (नींद की कमी) जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने मोबाइल फोन के दुरुपयोग को लेकर भी गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों में मानसिक तनाव पैदा कर रहा है, जो कई बार आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदमों का कारण भी बन रहा है।' कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि वे अपने भीतर होने वाले भावनात्मक बदलावों को पहचानें, उनसे डरें नहीं और आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी संकोच के विशेषज्ञों से परामर्श लें।इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। विद्यालय प्रशासन ने इस प्रकार के सत्रों को छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत लाभकारी बताया।

प्रवक्ता का वेतन डामटा से और ड्यूटी निदेशालय में

उत्तरकाशी (आरएनएस)। महानिदेशालय के शिक्षा समीक्षा केंद्र में कार्ययोजित जीआईसी डामटा में तैनात राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता की जल्द मूल विद्यालय में तैनाती नहीं होने पर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी को लिखे पत्र में अध्यापिका के विधिवत ट्रांसफर नहीं होने तक वेतन रोकने की मांग की है।

शिक्षक अभिभावक संघ के प्रस्ताव पर प्रधानाचार्य की ओर से अध्यापिका के वेतन रोकने के नोटिस और जनप्रतिनिधियों की ओर से अध्यापिका की मूल विद्यालय में वापसी के लिए दो बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत पर राजनैतिक संरक्षण की वजह से कार्यवाही न होने से प्रतिनिधियों में आक्रोश है। डामटा में राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता प्रियंका तोमर को दिसम्बर 2024 में शिक्षा समीक्षा केंद्र महानिदेशालय में कार्ययोजित किया गया जबकि अध्यापिका का वेतन मूल विद्यालय डामटा से निकल रहा है। उनके कार्ययोजित होने के बाद से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रहे 11वीं व 12वीं के 165 छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था दूसरे विषय के अध्यापक को दी गई है। 14 माह से विषय अध्यापक नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पीटीए अध्यक्ष विरेन्द्र सिंह ने बताया कि जन-जन की सरकार कार्यक्रम के दौरान भी अध्यापिका के खिलाफ शिकायत हुई है। कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है। नरेश रावत प्रभारी खण्ड शिक्षाधिकारी नौगांव, प्रधान ढुइंक त्रेपन रावत, प्रधान कांडी काजल चौहान, प्रधान सितवाड़ी शर्मिला, प्रधान खनाटी आशा देवी, प्रधान रिखाऊं सरोज, क्षेपंस शीतल गौड़, विजय राणा ने आदि जिलाधिकारी को लिखे शिकायती पत्र में अध्यापिका के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की मांग की है।

जीआरपी के हर थाने की हेल्पडेस्क में महिलाकर्मी की तैनाती होगी

हरिद्वार। जीआरपी के हर थाने की महिला हेल्पडेस्क पर 24 घंटे कम से कम एक महिलाकर्मी की तैनाती अनिवार्य होगी। मासिक अपराध गोष्ठी में एसपी-जीआरपी अरुणा भारती ने महिला अपराधों की त्वरित सुनवाई और कार्रवाई के लिए यह निर्देश दिए। जीआरपी सभागार में इस गोष्ठी की शुरुआत पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल ओपिन कुमार को जनवरी में सराहनीय कार्य के लिए 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' अवॉर्ड देकर हुई। इसके बाद एसपी-जीआरपी ने सभी थाना प्रभारियों को सचेत ऐप के अधिक से अधिक प्रचार, कार्मिकों का मासिक सम्मेलन कराकर उनकी समस्याओं का समाधान और ऑपरेशन-स्माइल में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस मामलों में नई गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई, जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया और वर्ष 2025 की लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। रेलवे स्टेशनों पर जहरखुरानी, टिकट धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा। हेल्पलाइन नंबर 112, 139 और 1930 के प्रचार-प्रसार, ट्रेनों में एस्कॉर्ट ड्यूटी और सुनसान रेलवे ट्रैकों पर नियमित पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। सभी थाना प्रभारियों को लंबित अभियोगों का त्वरित निस्तारण, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

रूट डायवर्जन पर बना है असमंजस, यात्री परेशान

कोटद्वार(आरएनएस)। फाल्गुनी कांवड़ यात्रा के दौरान कोटद्वार से सटी यूपी सीमा के नजीबाबाद में रूट डायवर्जन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर लगातार दूसरे दिन कोटद्वार डिपो प्रशासन और चालक-परिचालक असमंजस में रहे। इसका खामियाजा कई यात्रियों को भुगतना पड़ा। हरियाणा और पंजाब जाने वाली कोटद्वार रोडवेज डिपो की बसों के नजीबाबाद में नहर बाईपास से गुजरने अथवा वाया मुजफ्फरनगर से गुजारे जाने की स्थिति लगातार दूसरे दिन डिपो प्रशासन को स्पष्ट नहीं हो सकी।

दरअसल परंपरागत रूट से जाने वाली इन बसों में हरिद्वार और रुड़की समेत कुछ अन्य स्टॉपेज के यात्री सवार होते हैं। इन बसों को कांवड़ यात्रा के चलते वाया मुजफ्फरनगर गुजारने से हरिद्वार, रुड़की और कुछ अन्य स्टॉपेज प्रभावित होते हैं। कोटद्वार में चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर आदि स्टेशनों के लिए संचालित बसों में रास्ते की सवारियों को बैठाने को लेकर चालक-परिचालक असमंजस में रहे। उनका कहना था कि अगर वे बस में सवार रास्ते के स्टापेज के यात्री का टिकट बना देते हैं और नजीबाबाद से रूट डायवर्ट कर दिया जाता है तो उन्हें और यात्री को काफी परेशानी होती है। वहीं स्टाफ से सही जानकारी नहीं मिलने पर परेशान कुछ यात्रियों ने एआरएम से इसकी शिकायत करते हुए स्पष्ट जानकारी की। यात्रियों को बताया गया कि हरिद्वार और नजीबाबाद के बीच कांविड़यों की संख्या को देखते हुए बिजनौर प्रशासन द्वारा तात्कालिक निर्णय के तहत बसें गुजारी जा रही हैं। कुछ देर छटपटा कर यात्री हरिद्वार और नजीबाबाद के लिए रवाना हुए। यात्रियों ने बताया कि हरिद्वार और नजीबाबाद से ट्रेन अथवा अन्य वाहनों से वे गंतव्य तक पहुंचेंगे।

हल्द्वानी तहसील में 4 माह से नहीं हो रही जमीनों के दाखिल खारिज

हल्द्वानी (आरएनएस)। उत्तराखंड की सबसे व्यस्त तहसीलों में शुमार हल्द्वानी तहसील में पिछले चार महीनों से जमीनों का दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इससे 10,000 से अधिक रजिस्ट्रियों की दाखिल-खारिज लंबित हो गई हैं, जिसके कारण संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम लोग भारी परेशानी में हैं।

राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश जारी किए थे, ताकि पुरानी खामियों को दूर किया जा सके। लेकिन यह व्यवस्था धरातल पर लागू नहीं हो पा रही है, जिससे आम नागरिकों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी तहसील में प्रतिदिन औसतन 100 से अधिक रजिस्ट्रियां होती हैं। फिर भी दाखिल-खारिज न होने के कारण खतौनी अपडेट नहीं हो पा रही है। प्रभावित लोगों का कहना है कि नई रजिस्ट्री के बावजूद नामांतरण न होने से बैंक लोन, भवन निर्माण अनुमति, बिजली-पानी कनेक्शन, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य कानूनी कार्य ठप हो गए हैं। कई मामलों में पुरानी खतौनी के आधार पर लेन-देन जारी होने से धोखाधड़ी की आशंका भी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार, हल्द्वानी तहसील में करीब 10 हजार से अधिक जमीनों के दाखिल-खारिज लटके हुए हैं। जिन लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन दाखिल-खारिज नहीं हुआ, वे रोज तहसील के चक्कर काट रहे हैं।

जानकारों का मानना है कि जब तक सिस्टम में तकनीकी सुधार नहीं किए जाते और संबंधित अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तब तक यह समस्या जस की तस बनी रहेगी। रजिस्ट्रार कार्यालय भेजता था तहसील पहले रजिस्ट्री होने के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज रख लिए जाते थे। रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के बाद रजिस्ट्री की एक फोटोस्टेट कॉपी और मूल दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय भेजे जाते थे। तहसील कार्यालय में दाखिल-खारिज की निर्धारित तिथि दी जाती थी। निर्धारित दिन दाखिल-खारिज पूरा होने के बाद रजिस्ट्रीधारी अपनी मूल रजिस्ट्री ले जाता था। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद इस प्रक्रिया को पूरी तरह लागू करना मुश्किल साबित हो रहा है। तकनीकी खामियों और सिस्टम की अपर्याप्त तैयारी के कारण पुरानी व्यवस्था गड़बड़ा गई है, जिससे दाखिल-खारिज का कार्य ठप पड़ा हुआ है। मैन्युअल प्रक्रिया भी हुई बंद मैन्युअल प्रक्रिया भी बंदऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद कुछ लोग पीछे के दरवाजे से मैन्युअल रजिस्ट्री करवाने का प्रयास कर रहे थे। इस अनियमित कार्य को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को अवैध तरीके से आउटसोर्स किया गया था। हालांकि, कुछ समय पहले जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा की गई छापेमारी के बाद यह प्रक्रिया भी पूरी तरह बंद हो गई है।

कार्यशाला में विद्यार्थी वर्ग को दिए कॅरिअर बनाने के सुझाव

कोटद्वार(आरएनएस)। विकासखंड द्वारीखाल के जीआईसी पाली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अनूप डबराल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए छात्र जीवन से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। रुचि के अनुरूप विषय अथवा क्षेत्र का चयन करने पर सफलता जरूर मिलेगी। सीएचओ राधिका काला ने एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एवं विभिन्न मेडिकल कोर्स के संबंध में जानकारी दी। ताइक्कांडो प्रशिक्षक अनुष्का रावत ने खेलों में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं को खेल के क्षेत्र में विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। पीएचसी डाडामंडी की एएनएम सीता खणका ने अग्निवीर, होटल मैनेजमेंट, एलएलबी, बीबीए, योजना ध्यानी ने सेना में सीडीएस, एनडीए, शिक्षा के क्षेत्र में बीएड, अर्चना घिल्डियाल ने बीएमएस, एमबीबीएस आदि क्षेत्रों में कॅरिअर बनाने के संबंध में छात्र-छात्राओं की शंकाओं का समाधान किया।

ज्योतिर्मठ को केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग

चमोली(आरएनएस)। ज्योतिर्मठ विकास खंड को केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए पैनखंडा विकास संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। बताया इस संबंध में न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। सोमवार को ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष भरत सिंह कुंवर ने कहा कि ज्योतिर्मठ विकास खंड को केंद्रीय सूची में शामिल न करने पर लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए समन्वयक समिति का गठन भी किया गया है। कहा, मुख्यमंत्री को अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन भेजा जाएगा। इसके बाद 27 फरवरी को ज्योतिर्मठ में एक विशाल रैली आयोजित कर जन आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष देवेश्वरी शाह, ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी, प्रधान संगठन के अध्यक्ष मोहन बैजवाल, भगवती प्रसाद नंबूरी, राकेश भंडारी, कुशल कम्दी, अजीतपाल रावत, सुखदेव बिष्ट, समीर डिमरी, प्रवेश डिमरी, प्रकाश नेगी, जयप्रकाश भट्ट, बलवीर सिंह रावत आदि मौजूद रहे।

स्थानांतरण व पदोन्नति के लिए दिया धरना

चमोली(आरएनएस)। स्थानांतरण और पदोन्नति सहित अन्य मांगों के लिए लोनिवि मिनिस्ट्रीयल कर्मियों का कार्यबहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर लोनिवि निर्माण खंड थराली के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों ने विभागीय कार्यालय पर धरना दिया। कहा कि मांगों पर कार्रवाई न होने पर 13 फरवरी को देहरादून में विभागाध्यक्ष कार्यालय का घेराव व 18 फरवरी को सचिवालय कूच में भी थराली के कर्मी बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ कर्मचारी नेता देवराज सिंह राणा, रोशन लाल निराला, मोहन सिंह जलाल, कैलाश चन्द्र, राजेंद्र सिंह, त्रिलोक सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह आदि ने विचार व्यक्त करते हुए धरना दिया।

जनप्रतिनिधियों ने किया बवाल, योजनाओं के क्रियान्वयन पर उठाए सवाल

पौड़ी(आरएनएस)। जन-जन की सरकार कार्यक्रम में हर घर नल-हर घर जल व पीएम आवास योजना में पात्रों को लाभ नहीं दिए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया। कहा कि विभागों की मिली भगत से अपात्रों को लाभ और पत्रों को वंचित रखा जा रहा है। आक्रोशित जनप्रतिनिधि कार्यक्रम के दौरान ही धरने पर बैठ गए। वहीं सीडीओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

विकासखंड मुख्यालय पाबौ में सीडीओ गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में कार्यक्रम पूर्व निर्धारित समय पर आयोजित हुआ। जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना और हर घर नल योजना का लाभ नहीं मिलने पर कलुण सीट के जिपं सदस्य भरत रावत ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी पात्रों की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सर्दियों में ही जल संस्थान पेयजल व्यवस्था सुचारु नहीं कर पा रहा है। ऐसे में गर्मियों में स्थिति और भी विकट होनी तय है। इस मौके पर जिपं सदस्य कर्मवीर भंडारी, पूर्व प्रधान कुंज बिहारी पंत आदि मौजूद रहे।

समस्याओं का नहीं हुआ समाधान किया वॉटआउट- कार्यक्रम में समस्याओं का उचित समाधान नहीं होने से नाराज जनप्रतिनिधियों ने बैठक से वॉकआउट कर लिया। नाराज जनप्रतिनिधि बैठक कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज रावत ने कहा कि सरकारी कर्मचारी केवल योजनाओं का बखान कर वाहवाही लूट रहे हैं जबकि धरातल पर कई योजनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। चेतावनी दी कि यदि अगली बीटीसी बैठक तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों का उग्र विरोध किया जाएगा।

क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप रावत ने सीडीओ के समक्ष प्रावि पाबौ की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया। कहा कि विद्यालय की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन से पत्राचार किया गया। लेकिन आपदा और न ही किसी अन्य मद से धनराशि मिली। ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं।

सीडीओ गिरीश गुणवंत ने हर घर नल-हर घर जल योजना से जुड़ी शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा कि पीएम आवास योजना को लेकर जैसे ही लक्ष्य बढ़ाने के लिए शासन से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा, सभी पात्रों को इससे लाभांवित किया जाएगा। बताया कि कार्यक्रम में करीब 49 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया।

क्या आम नागरिक का जीवन मूल्यविहीन है?

●अधिवक्ता ललित शर्मा

क्या इस देश में आम इंसान के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? क्या केवल नेताओं, सेलिब्रिटियों और अधिकारियों के जीवन का ही मूल्य है? लोकतंत्र को जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन कहा जाता है, जहां सर्वोच्च सत्ता नागरिकों के हाथों में होती है, परन्तु वास्तविकता यह है कि ये आदर्श केवल प्रचार तक सीमित रह गए हैं और उनका वास्तविक क्रियान्वयन बहुत कम दिखायी देता है।

हाल ही में ग्रेटर नोएडा से बेहद हृदय विदारक और दुखद घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 16 जनवरी को 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की 20 फीट से अधिक गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर कर मौत हो गयी। मृतक इंजीनियर के पिता ने कहा अगर सिस्टम का थोड़ा भी समर्थन मिल जाता तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। उनका बेटा अपनी जिदंगी बचाने के लिए ढाई घंटे तक संघर्ष करता रहा और मौत से लड़ता रहा। युवराज ने बहुत हिम्मत दिखाई फोन से अपने पिता को इस बात की जानकारी दी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर आ गया और कार की छत पर लेट गया।

कुछ समय बाद उसके पिता, पुलिस और फायरब्रिगेड की टीम पहुंच गयी। लेकिन बिना उचित संसाधनो के दो घंटे तक कोई चरणबद्ध योजना नहीं बना पाए पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार और उसमें सवार व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। बिना तैयारी के घटनास्थल पर पहुंच गए ये हुआ युवराज की मौत हो गयी। एक पिता के सामने अपने जवान बेटे को खो देना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। घटना के बाद कार्यवाही और बड़े-बड़े आश्वासनों की घोषणाएं तो की जाती हैं, किन्तु दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में सुधार के कदम हमेशा किसी हादसे के बाद ही क्यों उठाए जाते हैं।

इस घटना से पहले एक ट्रक भी इस गड्डे में फंस गया था उसके बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये। अब सवाल स्वाभाविक है कि यदि युवराज की जगह कोई नेता, सेलिब्रिटी या अधिकारी होता, तो क्या उसके मामले में भी इतनी लापरवाही बरती जाती, या उसे बचाने के लिए तुरंत और विशेष कार्यवाही की जाती?

इस घटना के बाद जनकपुरी दिल्ली में कमल नामक व्यक्ति की 20 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गयी। उस दिन सिर्फ एक युवक नहीं डूबा, उस दिन कई दिल अपराधबोध और पीड़ा में डूब गए। उसकी माँ की गोद सूनी हो गई, पिता के सपने टूट गए, और समाज के सामने एक सवाल छोड़ गया क्या इंसान इतना असहाय हो सकता है कि सामने जिंदगी खत्म हो जाए और वह कुछ न कर सके? यह कोई नयी घटना नहीं है इस प्रकार की घटना निरंतर होती रहती हैं। कुछ वर्ष पहले मुखर्जी नगर में छात्रों की कक्षा में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ था। इसके पश्चात राजेन्द्र नगर में अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में पानी भर जाने से कई छात्रों की डूबकर जान चली गई। फिर भी ऐसी घटनाओं से कोई ठोस सबक नहीं लिया जाता है। घटना के तुरंत बाद कार्यवाही और सुधार को बड़े-बड़े आश्वासन दिए जाते हैं किंतु कुछ समय पश्चात ये सभी वायदे खोखले साबित हो जाते हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हमारे देश में आम नागरिक के जीवन की सुरक्षा को लेकर औपचारिक बातें और आश्वासन दिए जाते हैं, जबकि वास्तविक और ठोस कदम समय पर नहीं उठाए जाते। हर दुर्घटना के बाद प्रशासन जागता है, बड़े-बड़े वादे करता है, लेकिन कुछ समय बीतते ही सब भुला दिया जाता है। यदि लोकतंत्र सच में जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए है, तो सरकार और व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी आम नागरिक के जीवन की रक्षा होनी चाहिए। केवल संवेदनाएँ व्यक्त करने से नहीं, बल्कि समय रहते प्रभावी कार्यवाही और जवाबदेही तय करने से ही ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

भारत में ही सबसे पहले गणतंत्र था

अशोक प्रवृद्ध

बिहार का वैशाली (लिच्छवी गणराज्य) विश्व का पहला सफल गणतंत्र माना जाता है। जब यूनान में नगर-राज्यों की अवधारणा आकार ले रही थी, उससे बहुत पहले भारत में पूरी तरह विकसित गणतांत्रिक व्यवस्थाएँ मौजूद थीं।ऋ ऋग्वेद में 4० बार और अथर्ववेद में 9 बार गण' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज संख्या-बल और सामूहिक निर्णय की शक्ति को भली-भांति समझते थे। प्राचीन काल की सभा और समिति इस बात का प्रमाण हैं कि प्रजातंत्र के ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ उस समय भी सक्रिय थे।

गौरव की बात है कि भारत में गणतंत्र की अवधारणा केवल 195० से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें हमारी प्राचीन सभ्यता, वैदिक संस्कृति और इतिहास में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ सबसे पहले इसी धरती से मिला। हमारे ही देश में सर्वप्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ, जिसकी सफलता ने संसार का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऋग्वेद और अथर्ववेद में गण, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जो लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेती थीं। गण' शब्द का अर्थ ही जनता का समूह है, जहाँ शासक का चयन योग्यता के आधार पर होता था।

इतिहास के प्रमाण बताते हैं कि बिहार का वैशाली (लिच्छवी गणराज्य) विश्व का पहला सफल गणतंत्र माना जाता है। जब यूनान में नगर-राज्यों की अवधारणा आकार ले रही थी, उससे बहुत पहले भारत में पूरी तरह विकसित गणतांत्रिक व्यवस्थाएँ मौजूद थीं। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और भारत विभाजन की पीड़ा के बाद 26 जनवरी 195० को लागू हुआ हमारा संविधान आधुनिक भले ही हो, लेकिन उसकी आत्मा में वसुधैव कुटुंबकम्' और सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसी प्राचीन भारतीय भावनाएँ समाई हुई हैं। संविधान निर्माताओं ने पश्चिमी मॉडलों के साथ-साथ भारत की अपनी सांस्कृतिक विरासत और पंचायत परंपरा को भी महत्व दिया।

यह दिन केवल संविधान के लागू होने का उत्सव नहीं है, बल्कि उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का अवसर भी है, जिन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत का सपना देखा था। 26 जनवरी का यह राष्ट्रीय पर्व हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसी महान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, जिसने दुनिया को लोकतंत्र की दिशा दिखाई। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित गणतांत्रिक व्यवस्थाएँ यह सिद्ध करती हैं कि भारत में लोकतंत्र कोई आयातित विचार नहीं, बल्कि हमारी अपनी मिट्टी और वेदों की मौलिक देन है। यह भी सच है कि संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था की प्रेरणा पवित्र वेदवाणी से ही ली।

यह भारतीय गणतांत्रिक परंपरा की ऐतिहासिक जड़ों को उजागर करता है और साबित करता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र की अवधारणाएँ भारत में सहस्राब्दियों पहले से मौजूद थीं। संसार के आदिग्रंथ ऋग्वेद में 4० बार और अथर्ववेद में 9 बार गण' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज संख्या-बल और सामूहिक निर्णय की शक्ति को भली-भांति समझते थे। प्राचीन काल की सभा और समिति इस बात का प्रमाण हैं कि प्रजातंत्र के ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ उस समय भी सक्रिय थे। समिति आज की संसद या लोकसभा जैसी थी, जहाँ जनता और प्रतिनिधि नीति-निर्धारण के लिए एकत्र होते थे, जबकि सभा राज्यसभा या विद्वत परिषद की तरह कार्य करती थी, जहाँ अनुभवी लोग परामर्श और न्याय का दायित्व निभाते थे।

ऋग्वेद का वह मंत्र, जिसमें एकमत होकर निर्णय लेने की प्रार्थना की गई है, आधुनिक आम-सहमति के सिद्धांत का प्राचीनतम रूप माना जा सकता है। बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध के समय शलाका अर्थात मतपत्र द्वारा मतगणना का उल्लेख मिलता है, जो यह स्पष्ट करता है कि भारत में मतदान की प्रक्रिया अत्यंत विकसित थी। गण और संघ के माध्यम से बहुमत के आधार पर निर्णय लेना हमारी प्रशासनिक कुशलता का प्रतीक था। बाद में कुछ कारणों से व्यवस्था राजतंत्र की ओर मुड़ गई, लेकिन भारत की मूल चेतना हमेशा गणतांत्रिक बनी रही।

आज की पीढ़ी के लिए यह प्राचीन भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था अत्यंत प्रेरक है, क्योंकि अक्सर यह मान लिया जाता है कि लोकतंत्र पश्चिम की देन है। वास्तव में गण से गणतंत्र तक की यात्रा भारत की अपनी यात्रा है। इससे हम 26 जनवरी के वास्तविक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को समझ सकते हैं। भारत के प्राचीन राजनीतिक इतिहास और विकसित संवैधानिक ढाँचे यह सिद्ध करते हैं कि आज के युग में भी हमारे लोकतंत्र की सफलता के पीछे सहस्राब्दियों पुरानी सुव्यवस्थित शासन परंपरा है।

संसदीय शब्दावली की प्राचीनता इस तथ्य से समझी जा सकती है कि आज जिसे कोरम' कहा जाता है, उसे प्राचीन काल में गणपूरक' कहा जाता था। इसका अर्थ था कि न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति के बिना सभा मान्य नहीं होगी। सचेतक अर्थात व्हिप' की अवधारणा भी तब मौजूद थी, जिससे अनुशासन बना रहता था। महर्षि पाणिनि द्वारा वर्णित वृक, यौधेय और त्रिगर्त जैसे गणराज्य प्राचीन भारत के संघीय ढाँचे के सशक्त उदाहरण हैं। महाभारत में वर्णित अंधक-वृष्णि संघ, जिसके प्रमुख श्रीकृष्ण थे, एक उन्नत गणतंत्रीय संघीय व्यवस्था का प्रतीक है।

महाभारत यह भी बताता है कि जनसभा में प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार था, जो आज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रारंभिक रूप है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाना यह सिद्ध करता है कि सत्ता वंशानुगत नहीं, बल्कि योग्यता और जन-सहमति पर आधारित थी। कौटिल्य द्वारा लिच्छवी, वृज्जि और कम्बोज जैसे गणराज्यों का उल्लेख यह

▶▶ शेष पृष्ठ 5 पर

शब्द सामर्थ्य

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. जल छिड़कना, राजा के सिंहासन रोहन का अनुष्ठान 4. मवाद, पीब (अं) 6. जाति 7. हाथ से धीरे-धीरे ठोंकना, थपकना 9. कमल रोग से ग्रसित व्यक्ति (उ.) 11. किरण 12. छौंक, तड़का 13. दुखदायी, दर्दनाक 15. विवाद, कहासुनी, तकरार 18. समूह, दल, समुदाय 19. दण्ड 20. काजल 22. अनाथ, निराश्रित, यतीम 24. दुख, शोक 25. एक प्रसिद्ध सफेद पक्षी, वक 26. राज्य का विदेश में प्रतिनिधि।

ऊपर से नीचे

1. विचित्र, अद्‌भूत 2. अंदर ही अंदर हानि पहुंचाना 3. वचन, वाणी 4. गुमराह, जो रास्ते से भटक गया हो 5. मुलायम सिंह की पार्टी का संक्षिप्त नाम 8. ब्रह्मापुत्र एक प्रसिद्ध देवर्षि 10. कार्यावली, करस्तानी, प्रशंसनीय कार्य 13. दासी, नौकरानी, बांदी, गुलाम स्त्री 14. प्रवृत्त करने वाला, प्रेरित करने वाला, आविष्कारक 16. श्रीकृष्ण के बड़े भाई, हलधर 17. सामान (उ.) 21. संसार, दुनिया 22. समय, चमेली की जाति का एक पौधा और फूल 23. पराजित, परास्त।

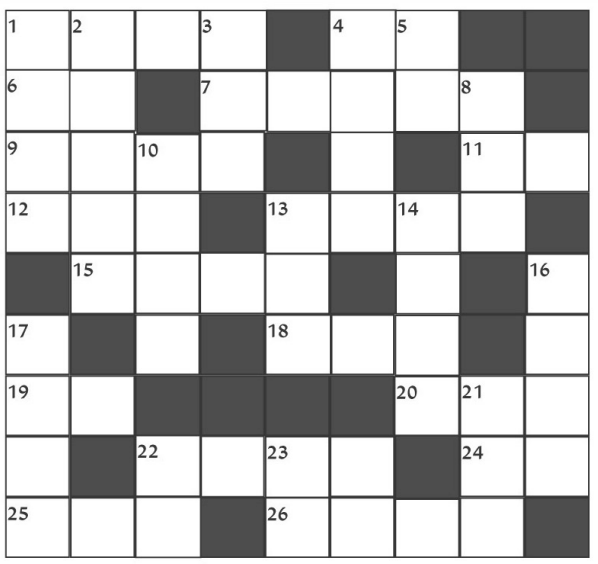

दि	क्क	त	■	आ	सा	न	■	आ
ल	■	मी	■	खि	■	सी	ख	ना
■	म	ज	बू	र	■	ह	■	जा
स	र्द	■	■	का	■	त	रा	ना
र	■	■	■	र	वि	■	ह	■
प	ह	ना	ना	■	ना	रा	ज	■
ट	■	■	क	शि	श	■	नी	ला
■	र	■	■	का	■	रा	■	य
खा	ति	र	दा	री	■	त	क्ष	क

दो दीवाने सहर में - मृणाल-सिद्धांत ने दिखाई बेफिक्र आशिकी

जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म दो दीवाने सहर में का खूबसूरत टीजर पहले ही दर्शकों के दिलों को जीत चुका है। एक रियल, सरप्राइजिंग और बेहद रिलेटेबल लव स्टोरी पेश करती यह फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट वैलेंटाइन ट्रीट लगती है, जो इम्परफेक्ट, कंफ्यूजिंग और खूबसूरती से उलझे हुए प्यार में विश्वास रखते हैं। जहां टीजर ने इस यूनिक रोमांस का टोन खूबसूरती से सेट किया, वहीं अब मेकर्स ने इसका पहला गाना आसमा' रिलीज किया है, इस सीजन का बेहद फ्रेश और नया साउंड ऑफ लव, जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की क्यूट केमिस्ट्री भी नजर आ रही है। यह गाना अपने आप में बिल्कुल अलग और क्लटर-ब्रेकिंग है, पारंपरिक लव सॉन्ग से हटकर। इसकी मीठी धुन और स्क्रीन पर दिखी कहानी के साथ आसमा' असली प्यार को जिंदा कर देता है। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल लगती है, जो गाने में सच्चापन और कनेक्ट होने वाला चार्म जोड़ देती है। जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की खूबसूरत आवाज़ के साथ आसमा' सीधे दिल को छू जाता है। हेशम अब्दुल वहाब की खूबसूरत कंपोज़िशन गाने के रोमांटिक जज्बे को और बढ़ा देती है, वहीं अभिरुचि चंद के भावपूर्ण लिरिक्स इसे ऐसे गाने में बदल देते हैं जो लंबे समय तक याद रहता है और इस सीजन का फ्रेश और नया साउंड ऑफ लव साबित होता है। जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस पेश करते हैं दो दीवाने शहर में, जिसमें लीड रोल में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी हैं। फिल्म का निर्देशन रवि उद्यवार ने किया है और इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने रवि उद्यवार फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। दो दीवाने शहर में 20 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी।

द केरल स्टोरी 2 का मोशन पोस्टर जारी, रिलीज तारीख से उठा पर्दा

अभिनेत्री अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी साल 2023 में रिलीज हुई थी जिसे लोगों द्वारा खूब सराहा गया था। निर्माता इस कहानी को खत्म न करते हुए दूसरी किस्त के साथ ला रहे हैं जिसे द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड शीर्षक दिया गया है। फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। साथ ही इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठाया गया है। दूसरी किस्त का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने द केरल स्टोरी 2 का मोशन पोस्टर जारी किया है जो भावनात्मक और गहन कहानी लाने का वादा करता है। टीजर में महिलाओं के पीड़ा से भरे चेहरों को दर्शाया गया है, जो डर, आंसू और बढ़ते गुस्से की तरफ ध्यान खींचते हैं। इस बार नए मुख्य कलाकारों को शामिल किया है जिनमें उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा शामिल हैं। यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

डॉन 3 को ठंडे बस्ते में डालकर इस फिल्म में जुटे फरहान अख्तर, बनाई ये योजना

फरहान अख्तर की डॉन 3 का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। रणवीर सिंह के अचानक पीछे हटने के बाद फिल्म फिर ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। बीच में खबर थी कि फिल्म के लिए ऋतिक रोशन और शाहरुख खान से बातचीत चल रही है, लेकिन अब चर्चा है कि फरहान इससे ध्यान हटाकर अपनी दूसरी परियोजना पर काम शुरू करना चाहते हैं। वह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म जी ले जरा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान को लगता है कि डॉन 3 की कास्टिंग होना जरूरी है, लेकिन वह आश्वत होना चाहते हैं कि इस भूमिका को कौन निभाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभिनेता फिलहाल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जी ले जरा को पटरी पर लाना चाहते हैं। इसमें मुख्य किरदार के लिए वह प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ से दोबारा संपर्क कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। खबरों के मुताबिक, जी ले जरा की स्क्रिप्ट तैयार है, फाइनल भी हो चुकी है, लेकिन निर्माताओं को शूटिंग की तारीखें तय करने में मुश्किल आ रही है। एक समय पर प्रियंका, आलिया और कैटरीना के साथ शूट करने के लिए तारीखों का तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तारीखें मेल खाती हैं, तो शूटिंग 2026 के दूसरी छमाही से शुरू हो सकती है। फरहान इस चुनौती को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं।

भारत में ही सबसे पहले गणतंत्र था

◀◀ पृष्ठ 4 का शेष

दर्शाता है कि मौर्य काल तक भी ये गणराज्य प्रभावशाली थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपद' शब्द जनता की सर्वोच्चता को रेखांकित करता है।

स्पष्ट है कि भारत में गणतंत्र केवल एक शासन-व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन-शैली थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाना वास्तव में उसी वैदिक, महाभारतकालीन और मौर्यकालीन लोकतांत्रिक चेतना का आधुनिक पुनर्जागरण था। वैशाली और लिच्छवी जैसे उदाहरण यह प्रमाणित करते हैं कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। इसलिए 26 जनवरी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों की इस गणतांत्रिक यात्रा के सम्मान का दिन है, जिसे समझना और सहेजना आज और भी अधिक आवश्यक है।

श्रुति हासन : विरासत से नहीं, टैलेंट से बनीं सफल अभिनेत्री और गायिका

भारतीय सिनेमा में कुछ नाम ऐसे हैं, जो सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं हैं। ये नाम अपनी बहुआयामी प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाते हैं। श्रुति कमल हासन ऐसी ही एक शख्सियत हैं। एक सफल अभिनेत्री, गायिका, संगीतकार और परफॉर्मर, जिनकी पहचान केवल एक स्टार किड के तौर पर नहीं, बल्कि एक मेहनती और टैलेंटेड आर्टिस्ट के रूप में बनी है। 1986 में जन्मीं श्रुति हासन, भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन और मशहूर अभिनेत्री सारिका ठाकुर की बेटी हैं। हासन परिवार में जन्म लेने के बावजूद श्रुति ने अपनी राह खुद बनाई। वह न सिर्फ एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक स्थापित गायिका और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। श्रुति ने चेन्नई के एबाकस मोंटेसरी स्कूल में पढ़ाई की और दसवीं तक वहीं शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मुंबई के सेंट एंड्रयूज कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई की। बचपन से ही उन्हें संगीत और सिनेमा में गहरी रुचि थी। इसी लगाव ने उन्हें आगे चलकर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया, जहां उन्होंने संगीत की औपचारिक ट्रेनिंग ली।

महज छह साल की उम्र में श्रुति हासन ने अपने पिता की फिल्म थेवर मगन (1992) में पहला गाना गाया, जिसे इलैया राजा ने कंपोज किया था। इसके बाद स्कूल के दिनों में उन्होंने हिंदी फिल्म चाची 420 (1997) में भी गायन किया। साल 2000 में कमल हासन के निर्देशन में बनी फिल्म हे राम में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और उसी फिल्म के लिए हिंदी और तमिल में टाइटल थीम रामा रामा भी गाई।

एक अभिनेत्री के तौर पर श्रुति ने वयस्क भूमिका में डेब्यू 2009 में बॉलीवुड फिल्म लक' से किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा की ओर रुख किया और यहीं से उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा।

श्रुति को असली पहचान तेलुगु फिल्म अनागनगा ओ धीरुडु (2011) से मिली। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ दिलाया। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। रेस गुर्रम (2014) में दमदार भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु मिला। कुल मिलाकर श्रुति के नाम तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स सहित कई सम्मान दर्ज हैं।

हिंदी सिनेमा में श्रुति हासन ने डी-डे, रामैया वस्तावैया, गब्बर इज बैक, वेलकम बैक, रॉकी हैंडसम जैसी फिल्मों में काम किया। जहां कुछ फिल्मों को समीक्षकों की सराहना मिली, वहीं कुछ बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। अभिनय के साथ-साथ संगीत श्रुति हासन की पहचान का अहम हिस्सा है। वह एक स्थापित पार्श्व गायिका हैं। साल 2009 में उन्होंने अपने पिता के प्रोडक्शन उन्नैपोल ओरुवन से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर भी डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का म्यूजिक भी तैयार किया और बैंड के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई।

श्रुति हासन का सफर इस बात का प्रमाण है कि पहचान नाम से नहीं, काम से बनती है और सुर, स्क्रीन और संवेदनाओं का यह संगम अभी और भी लंबा चलना है।

मुझे पर्दे पर अपनी उम्र की परवाह नहीं: मोना सिंह

जस्सी जैसी कोई नहीं टीवी शो से लोकप्रिय हुईं मोना सिंह इन दिनों धड़ाधड़ फिल्में और सीरीज कर रही हैं। हाल ही में उन्हें बॉर्डर 2 और हैप्पी पटेल जैसी फिल्मों में देखा गया। अब उनकी सीरीज कोहरा 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। प्रमोशन के दौरान 40 वर्षीय मोना ने पर्दे पर 50 और 60 साल की उम्र के किरदार पर बात की। साथ ही सिनेमा जगत में महिलाओं को एक्सपायरी डेट दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी।

अभिनेत्री बोलीं, मुझे पर्दे पर अपनी उम्र की परवाह नहीं। सच में नहीं, क्योंकि मैं बहुत आत्मविश्वासी हूं और मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं जोखिम लेती रहती हूं। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, आप पर्दे पर इतनी उम्रदराज क्यों दिखती हैं? मैं कहती हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो किरदार है जिसे मैं निभा रही हूं। ये मुझे उत्साहित करता है।

उन्होंने आगे कहा, सिनेमा में महिलाओं के लिए एक समय सीमा तय कर दी जाती है। ये बेहद दुखद है। 60 साल के अभिनेता अभी भी रोमांटिक मुख्य किरदार निभा सकते हैं, लेकिन अभिनेत्रियां नहीं। हालांकि मुझ इसकी परवाह नहीं क्योंकि मैं वैसी बनना ही नहीं चाहती थी। गुंजित चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा द्वारा निर्मित कोहरा 2 ने नेटफ्लिक्स पर 11 फरवरी को दस्तक दी है जिसमें मोना सीरीज में दमदार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं।

घोड़े-खच्चरों के पंजीकरण के लिए सीएम को भेजा ज्ञापन

चमोली(आरएनएस)। वर्ष 2026 की केदारनाथ यात्रा के लिए चमोली जनपद के घोड़ा-खच्चर संचालकों ने यात्रा पंजीकरण करने की मांग उठाई है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। सामाजिक कार्यकर्ता भरत सिंह, राकेश सैंजवाल, प्रदीप बर्त्वाल आदि ने ज्ञापन में कहा कि घोड़ा संचालकों ने मुख्यमंत्री से जनपद से 1000 घोड़े-खच्चर सवारियों व 500 खच्चर माल ढुलान के लिए पंजीकृत कराने की मांग की है। कहा, इस वर्ष भी संचालक स्वरोजगार के लिए अपने घोड़े-खच्चरों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की ओर से पंजीकरण कराया जा रहा है। कहा, पिछले तीन साल से रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन संचालकों का पंजीकरण नहीं करा रहा है जबकि प्रतिवर्ष संचालक प्रतिवर्ष अपने घोड़े-खच्चरों के साथ गौरीकुंड और सोनप्रयाग पहुंचते हैं। उन्हें इससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

आगामी केदारनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पशुपालन विभाग घोड़े-खच्चरों की स्वास्थ्य जांच, पशुधन बीमा, ग्लैंडर्स व इक्वायन इंफ्ल्यूंजा रोग की निगरानी के लिए विभिन्न जगहों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. असीम देव ने बताया कि शिविर 23 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होंगे। ज्योतिर्मठ के अंतर्गत करछी, तुगासी व करछों में 23 से 26 फरवरी, थैंग में 27 फरवरी, चांई में एक मार्च, सलूड़-डुंगरा में छह मार्च, उर्गम व कलगोठ में सात मार्च, पल्ला जखोला में नौ मार्च, ईराणी में 23 फरवरी, पगना में 25, निजमुला में 26, सैंजी में 27, पीपलकोटी में एक मार्च, बिरही में 6 मार्च, मैठाणा में सात मार्च, कनोल में 23 फरवरी, पल्टिंगधार में 24, घूनी में 25, सितेल में 26, ल्वाणी में 27, पगना में एक मार्च, भेंटी में 6 मार्च, बांजबगड़ में 7 मार्च, सेरा में नौ मार्च, सेमा में 10 मार्च, कांडई में 11 मार्च व बूरा में 12 मार्च को स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे।

तीन दिन में अतिक्रमण चिह्नित करने के निर्देश

रुद्रपुर(आरएनएस)। नगर के प्रमुख चौराहों को जाममुक्त करने के लिए राजस्व, नगरपालिका, एनएचएआई व पुलिस टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया। एसडीएम रविंद्र जुंवाठा की अध्यक्षता में तिरंगा चौक, बिजटी चौक, महाराणा प्रताप चौक का निरीक्षण किया गया। सितारगंज के तिरंगा चौक, बिजटी, चौक, महाराणा प्रताप चौक समेत पूरे मार्ग में जाम लगा रहता है। सिडकुल के भरी वाहन, खनन वाहन इसी मार्ग से चलते हैं। सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण भी है। पिछले दिनों सीडीओ ने पालिकाध्यक्ष सुखदेव सिंह, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल समेत जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया था। तब एनएचएआई के अफसरों के साथ पुनः निरीक्षण कर समाधान के निर्देश सीडीओ ने दिये थे। निरीक्षण में तीन दिन में अतिक्रमण चिह्नित करने के निर्देश दिए। ताकि जाम से निजात का निराकरण हो सके। यहां एनएचएआई के साइड इंजीनियर तुषार गुप्ता, ईओ प्रतिभा कोहली, कोतवाल सुंदरम शर्मा, एलआइयू इंचार्ज भास्कर बडोला मौजूद रहे।

सू- दोकू क्र.040

	2		6		8		3	
9		8		3		4		
							5	
5		2			7		6	
	8		4			1		3
				9				
8			9				1	
	5			1		6		2
		1	7				4	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र. 39 का हल

2	6	3	8	1	4	9	7	5
9	5	4	2	6	7	3	1	8
8	7	1	9	3	5		6	2
6	2	7	5	4	8	4	3	9
3	9	8	6	7	1	2	5	4
4	1	5	3	2	9	6	8	7
5	3	2	4	8	6	7	9	1
1	8	6	7	9	2	5	4	3
7	4	9	1	5	3	8	2	6

गौशाला निर्माण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी

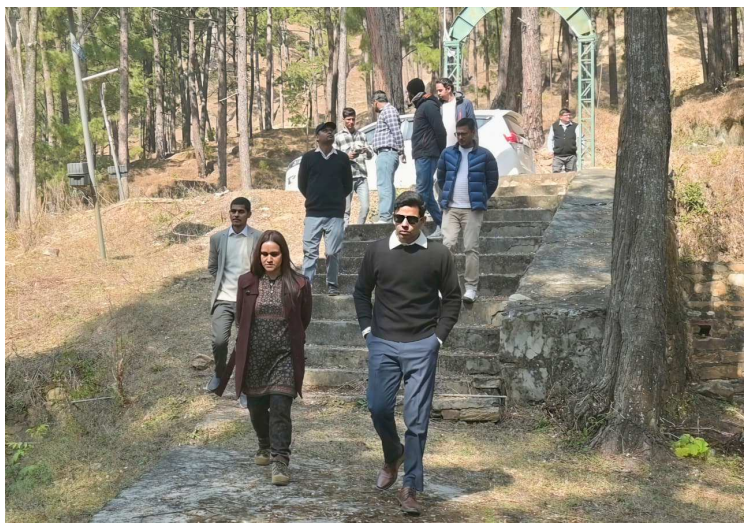

अल्मोड़ा(आरएनएस)। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय चारा एवं बीज उत्पादन प्रक्षेत्र भैंसवाड़ा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग की गतिविधियों के साथ संचालित और निर्माणाधीन गौशालाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गौशाला निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा गौशाला के विस्तार को स्वीकृति दी जा चुकी है, ऐसे में अधिकारी इस कार्य को गंभीरता से लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर रहकर संपूर्ण ड्राइंग और कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और कहा कि गौशाला निर्माण को संवेदनशीलता के साथ किया जाए, जिम्मेदारियों से बचने का रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंशुल सिंह ने कहा कि 100 गोवंश क्षमता वाली प्रस्तावित गौशाला के निर्माण से आवारा गोवंश की समस्या के समाधान में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने इसी क्षेत्र में एक और गौशाला के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि भैंसवाड़ा क्षेत्र गौशाला निर्माण के लिए अनुकूल है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भैंसवाड़ा फार्म तक पहुंच मार्ग की स्थिति का भी संज्ञान लिया और उसके निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर आगणन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। इस अवसर पर पशुपालन विभाग, कार्यदाई संस्था जिला पंचायत के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी

चमोली(आरएनएस)। जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज रडुवा चांदनीखाल में जन-जन की सरकार-जन-जन के द्वार अभियान के तहत बहउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 60 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सरकारी विभागों की ओर से शिविर में स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनता से सीधा संवाद किया। उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागाध्यक्षों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर दर्जाधारी रामचंद्र गौड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष राधा रावत, रंजन सिंह, ग्राम प्रधान हरिकृष्ण प्रसाद, बीडीओ शिव सिंह, तहसीलदार जितेंद्र रावत आदि मौजूद रहे।

नैनीताल पुलिस ने 33 लापता बरामद किए

हल्द्वानी(आरएनएस)। नैनीताल जिले में लापता हुए 33 लोगों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सात साल के भीतर जिले से 161 लोग लापता हुए। जिनकी तलाश में पुलिस अभियान चला रही है। सीओ सिटी और ऑपरेशन स्माइल के नोडल अधिकारी अमित कुमार सैनी के नेतृत्व में गठित पांच टीमों की ओर से चलाए गए अभियान में बिहार, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली से गुमशुदा लोगों को तलाशा गया है। ऑपरेशन के लिए पुलिस की चार और एक टेक्निकल टीम ने काम किया। टीम में एसआई कुमकुम धानिक, एएसआई आनंद बल्लभ जोशी, प्रेम बल्लभ जोशी व हरभजन सिंह और कांस्टेबल दीपक भारद्वाज शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस बहुउद्देशीय भवन में सीओ ने स्टेकहोल्डर विभागों, एनजीओ के साथ गोष्ठी की। इसमें गुमशुदा लोगों की ढूंढखोज को चल रहे अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए।

कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक है एआई, दुरुपयोग से बचना जरूरी

चमोली(आरएनएस)। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से सेफर इंटरनेट डे के मौके पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग व डिजिटल जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने कहा, एआई का सही उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है लेकिन इसके दुरुपयोग से बचना अत्यंत आवश्यक है। कार्यशाला में अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुशीला न फिशिंग वेबसाइट्स, ओटीपी, यूपीआई फ्रॉड,ऑनलाइन स्कैम, एआई के दुरुपयोग व डीपफेक जैसी चुनौतियों की जानकारी दी।

सीबीआरआई रुड़की ने मनाया 80वां स्थापना दिवस

रुड़की(आरएनएस)। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की ने अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया। संस्थान के रवींद्रनाथ टैगोर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और छात्रों ने संस्थान की आठ दशकों की यात्रा और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को साझा किया। समारोह में संस्थान के निदेशक प्रो. आर प्रदीप कुमार और अन्य अतिथियों ने सीबीआरआई के प्रतीक चिह्न का अनावरण किया। यह नया मोनोग्राम संस्थान की आधुनिक पहचान और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस अवसर पर खानग्पाद लिविंग हाउस ऑफ लद्दाख शीर्षक पुस्तक सहित वर्ष 2024 व 2025 के शोध प्रकाशनों का विमोचन किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार और खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व निदेशक डॉ. एन. गोपालकृष्णन ने सीबीआरआई द्वारा आपदा न्यूनीकरण और उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए विकसित उन्नत मॉडलिंग तकनीकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान की भू-तकनीकी और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता वैश्विक स्तर की है। विशिष्ट अतिथि दुर्योधन सेठी वित्त अधिकारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा ने संस्थान की प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय पारदर्शिता को उसकी मजबूत पहचान का आधार बताया। समारोह का समापन सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ। इसमें संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं।

कार्यक्रम का संचालन मुख्य वैज्ञानिक डॉ. डी. पी. कानूंगो ने किया। प्राथमिकता = थ्रीडी प्रिंटिंग और टिकाऊ तकनीक संस्थान के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि संस्थान थ्रीडी कंक्रीट प्रिंटिंग, डिजिटल डिजाइन और जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण तकनीकों को भविष्य की प्राथमिकता बताया। आपदा प्रबंधन पर वैज्ञानिक कार्यशाला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में क्रायोस्फेरिक आपदाओं में प्रगति विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें एनडीएमए के निदेशक डॉ. ओ. पी. मिश्रा ने हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन और रॉक-आइस घटनाओं से निपटने के लिए तकनीकी समाधानों पर चर्चा की।

कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध दर्ज किया!

संवाददाता

देहरादून। मण्डल सचिव कामरेड नरेश गुरुंग और शाखा अध्यक्ष तेजिन्दर सिंह के नेतृत्व में देहरादून शाखा द्वारा सभी विभागों में जा कर कार्य के साथ साथ काला फीता बांधकर विरोध किया।

आज यहां केंद्र सरकार द्वारा चार लेबर कोड लागू करने के विरोध में देशभर की मजदूर ट्रेड यूनियनो द्वारा देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। इस मौके पर एआईआरएफ/एनआरएमयू के कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर और मण्डल सचिव कामरेड नरेश गुरुंग और शाखा अध्यक्ष तेजिन्दर सिंह के नेतृत्व में देहरादून शाखा द्वारा सभी विभागों में जा कर कार्य के साथ साथ काला फीता बांधकर विरोध किया। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की निंदा की और सभी को संघर्षों हेतु जागरूक रहने की अपील की। चार लेबर कोड मंजूर नहीं ,तुरंत वापिस लिए जाएं इनके लागू होने पर कर्मचारियों की छंटनी आसान होगी,हड़ताल पर प्रतिबन्ध, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा,वेतन प्रणाली में संशोधन करके वेतन कम, असंगठित यूनियन कमजोर और असहाय और इंडस्ट्री में मजदूर विरोधी नीतियों का बोलबाला रहेगा। लेबर कोड का विरोध करके केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली की निंदा की।

तीन पेटी शराब के साथ दो गिरफ्तार

संवाददाता

टिहरी॥ पुलिस ने तीन पेटी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार को सीज कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार जनपद में अवैध मादक पदार्थों/शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चम्बा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा मसूरी रोड स्थित आई.टी.आई. तिराहा चम्बा पर चेकिंग के दौरान एक मारुति कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से 144 पव्वे (03 पेटी) अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मौके से कार सवार 02 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बताया कि वे उक्त शराब को झड़ीपानी क्षेत्र में बिक्री हेतु ले जा रहे थे। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज कर दिया गया है। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम बलदेव चन्द रमोला पुत्र कुलवीर चन्द रमोला निवासी ग्राम सौड़, जड़ीपानी, चम्बा टिहरी गढ़वाल, अमित आर्य पुत्र कौओरु आर्य निवासी सौड़ जड़ीपानी, चम्बा टिहरी गढ़वाल बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया।

आपराधिक घटनाओं से देवभूमि की संस्कृति हो रही कलंकितः जोशी

संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस के पूर्व सचिव महेश जोशी ने कहा कि लगातार हो रही अपराधिक घटनाओं से देवभूमि की संस्कृति कलंकित हो रही है।

आज यहां प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव महेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं बिगड़ती कानून व्यवस्था से देवभूमि की संस्कृति हो रही कलंकित और प्रदेश अपना स्वरूप खो रहा। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है चौदह दिन में चार हत्याएं देहरादून जिले में हो चुकी है। हल्द्वानी में डबल मर्डर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भय का माहौल है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश सरकार की जन विरोधी युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ बढ़ती बेरोजगारी दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय महिला अपराधों में बढ़ोतरीबिगड़ती कानून व्यवस्था बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं महंगाई, भ्रष्टाचार, मनरेगा रोजगार गारंटी कानून पुनः लागू हो जैसे प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस 16 फरवरी को राजभवन घेराव करेगी जिसमें प्रदेश से हजारों लोग शिरकत करेंगे।

मुख्य सचिव ने वित्त समिति की बैठक में दिये जरूरी दिशा निर्देश

संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने वित्त समिति की बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिये।

आज यहां मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के योजना प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागीय उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों के साथ ही अन्य संबंधित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्ति किया जाये। मुख्य सचिव ने जनपद चम्पावत के अन्तर्गत रोडवेज स्टेशन चम्पावत में आधुनिक सुसज्जित स्टोरी पार्किंग व शॉपिंग कॉम्प्लैक्स के निर्माण लागत 64.94 करोड रूपये के प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान करते हुए इसका नाम सिटी सेंटर चम्पावत रखे जाने के निर्देश दिये। उन्होने इसमें यात्रियों एवं स्थानीय जनता को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने, स्थानीय उत्पादों के विपणन की व्यवस्था तथा पार्किंग स्थल पर रोडवेज की बसों के साथ ही टैक्सी पार्किंग की भी व्यवस्था करने को कहा ताकि इससे आम जनता को और अधिक सुविधा हो सके। मुख्य सचिव ने जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत टिहरी मुख्यालय के माल रोड़ में फसाड कार्य रेलिंग्स, पाथ, स्ट्रीट लाइट, शौचालय निर्माण किये जाने आदि के प्रस्तावित कार्यों हेतु 11.25 करोड कि संस्तुति प्रदान करते हुए कहा कि टिहरी नगर में फसाड़ कार्य, रेलिंग्स, पाथ, स्ट्रीट लाईट एवं शौचालय का निर्माण से आम जनमानस/पर्यटकों को सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त व्यय वित्त समिति की बैठक में मुख्य सचिव द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 में राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराये जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु 52.84 करोड़, जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में किमतोली से रौशाल मोटर मार्ग में हॉट मिक्स का कार्य हेतु 12.15 करोड, जनपद ऊधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत एनएच 109 में पं. राम सुमेर शुक्ला राजकीय मेडिकल कॉलेज से अटरिया माता मन्दिर मोड, सिडकुल एवं आनंदपुर होते हुए एसएच44 तक मार्ग के किमी. 5.000 से 12.255 तक पुनः निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को 23.12 करोड़ जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र क्षेत्र किच्छा के शिमला पिस्तौर कुरैया मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को 20.17 करोड़ की संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव द्वारा कुम्भ मेला-2027 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत खड़खड़ी शमशान घाट जाने वाले मार्ग पर सूखी नदी पर स्थित कॉजवे के स्थान पर डबल लेन सेतु का निर्माण हेतु शहरी विकास विभाग को 13.22 करोड, कुम्भ मेला-2027 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में मायापुर स्क्रैप चैनल पर दक्षद्वीप एवं बैरागी कैम्प को जोडने वाले पूर्व निर्मित सेतु के डाउनस्ट्रीम में 60 मी. स्पान स्टील गर्डर डबल लेन सेतु के निर्माण हेतु शहरी विकास विभाग को 12.46 करोड की भी संस्तुति प्रदान की गई। इस अवसर पर सचिव नितेश झा, डॉ पंकज कुमार पाण्डे, डॉ आर. राजेश कुमार, वी. षणमुगम, विषेश सचिव अजय मिश्रा, मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका सहित विभिन्न विभागों के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

36वां सड़क सुरक्षा माहः पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान

टिहरी (सं)। 36वें सडक सुरक्षा माह के अन्तर्गत पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। आज यहां पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी यातायात के पर्यवेक्षण में "36वां सड़क सुरक्षा माह" के अवसर पर यातायात पुलिस द्वारा जनपद में विशेष अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग-07 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर सघन चेकिंग एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 250 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए, जिससे रात्रि में दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। करीब 300 वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। वाहन चालकों को वाहनों में रिफ्लेक्टर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। शराब पीकर वाहन न चलाने एवं भार वाहनों में सवारी न बैठाने के संबंध में सख्त हिदायत दी गई। आमजन को जागरूक करने हेतु सड़क सुरक्षा संबंधी पंपलेट भी वितरित किए गए।

इएमए की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने ली शपथ

संवाददाता

देहरादून। इएमए की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण कार्यक्र आयोजित किया।

आज यहां परेड ग्राउंड स्थित एक क्लब के सभागार में इएमए देहरादून की नव निर्वाचित जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसका शुभारम्भ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. के पी एस चौहान, राष्ट्रीय महासचिव डा. एन एस टाकुली, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डा. वी एल अलखानिया, प्रदेश अध्यक्ष डा. मुकेश चौहान, प्रदेश महामंत्री डा. एम टी अंसारी, प्रदेश संगठन मंत्री डा. एस पी डोभाल, उ प्र राज्य प्रभारी डा. सुरेंद्र कुमार ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित करके किया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में डा. सी पी रतूडी को जिला अध्यक्ष , डा. एम एस कश्यप, डा. कैलाश बडथवाल को जिला उपाध्यक्ष , डा. आदर्श शर्मा को जिला महामंत्री, अब्दुल गफूर को जिला सचिव, डा. कमलेश खंडूडी को जनपद प्रभारी, डा. श्रवण कुमार को जिला संगठन मत्रीं, डा. बिवस अधिकारी को जिला मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. के पी एस चौहान ने दिलायी। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. के पी एस चौहान ने कहा कि रोगी के लिए चिकित्सक एक भगवान का रुप होता है। चिकित्सक द्वारा रोगी को उपयुक्त समय देकर रोगी के साथ मधुर व्यवहार एवं संवाद कायम करना चाहिए। समारोह का संचालनध इ एम ए केंद्रीय कार्यालय प्रभारी डा ऋचा आर्य ने किया। कार्यक्रम मे सुखबीर द्विवेदी, डा. वी के सैनी, डा. नेपाल सिंह, डा. रामकुमार, डा. एन एस नेगी, डा. आई एच अंसारी, डा. डी सी आर्य, डा. एस के विश्वास, डा. बेदना विश्वास, श्रीपाल सिंह, डा. शंभूनाथ पोखरियाल, डा. सुल्तान फैज, डा. चांद उस्मान, डा. अशोक कुशवाहा, डा. विक्रम चौहान, डा. ए पी अग्रवाल, डा. गुलाम साबिर आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखंड के सांसदों की केवल 18 प्रतिशत सांसद निधि हुई खर्च

❑सांसदों द्वारा प्रस्तावित 232 कार्य स्वीकृत ही नहीं हुये, 87 कार्य प्रारंभ नहीं हुये

कार्यालय संवाददाता

काशीपुर। उत्तराखंड के लोकसभा तथा राज्यसभा के वर्तमान सांसदों की आवंटित सांसद निधि की कुल धनराशि में दिसंबर 2025 तक केवल 18 प्रतिशत धनराशि ही खर्च हुई है। इसमें पूर्ण कार्यों तथा चल रहे कार्यों पर खर्च ध नराशि शामिल हैं। सांसदों द्वारा प्रस्तावित 232 कार्य अधिकारियों ने स्वीकृत ही नहीं किये है तथा स्वीकृत कार्यों में से 87 कार्य दिसम्बर 2025 तक प्रारंभ भी नहीं हुये है। यह खुलासा सांसद निधि के नोडल विभाग ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तराखंड कार्यालय द्वारा सूचना अधि कार कार्यकर्ता नदीम उददीन एडवोकेट को उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड के ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से सांसद निधि खर्च सम्बन्धी सूचना चाही थी। जिसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त प्रशासन, हेमन्ती गुंजियाल द्वारा अपने पत्रांक 245531 के साथ सांसद निधि खर्च के दिसम्बर 2025 के विवरण की प्रति उपलब्ध करायी है। जिसमें दिसम्बर 2025 के अंत तक की उत्तराखंड के लोक सभा सांसदों की सांसद निधि खर्च का विवरण दिया है।

नदीम को उपलब्ध विवरण के अनुसार दिसम्बर 2025 तक उत्तराखंड के कुल 8 सांसदों को 95.90 करोड़ की सांसद निधि आवंटित हुई है। इसमें 49 करोड़ 5 लोकसभा सांसदों तथा 46.90 करोड़ 3 राज्यसभा सांसदों को आवंटित हुई है। उत्तराखंड के सांसदों के वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण कार्यों पर कुल 7.08 करोड़ तथा चल रहे अपूर्ण कार्यों पर दिसम्बर 2025 तक कुल 10.65 करोड़ की धनराशि खर्च हुई है जो कुल आवंटित धनराशि का 18 प्रतिशत है। इसमें लोकसभा के 5 सांसदों की पूर्ण कार्यों पर 2.089 करोड़ तथा अपूर्ण तथा चल रहे कार्यों पर 1.191 करोड़ की ध नराशि खर्च दर्शायी गयी है जो कुल आवंटित धनराशि की केवल 7 प्रतिशत है। राज्यसभा के 3 सांसदों की आवंटित निधि में से पूर्ण कार्यों पर खर्च 4.99 करोड़ तथा चल रहे कार्यों पर 9.46 करोड़ दर्शाया गया है जो कुल आवंटित निधि का 31 प्रतिशत है। सांसद वार सांसद निधि खर्च के मामले में लोकसभा सांसदों में सर्वाधिक निधि 18 प्रतिशत खर्च करने वाले नैनीताल-उधमसिंह न ग र सांसद अजय भट्ट हैं जबकि दूसरे स्थान पर 14 प्रतिशत सांसद निधि खर्च टिहरी गढ़वाल सांसद श्रीमति माला राज लक्ष्मी शाह है। अन्य तीनों लोकसभा सांसदों गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की शून्य, अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा तथा हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत की दिसम्बर 2025 तक सांसद निधि से एक प्रतिशत से कम धनराशि खर्च दर्शायी गयी है। राज्यसभा सांसदों में सर्वाधिक सांसद निधि 47 प्रतिशत नरेश बंसल, दूसरे स्थान पर 27 प्रतिशत कल्पना सैनी तथा तीसरे स्थान पर 6 प्रतिशत महेन्द्र भट्ट की दिसम्बर 2025 तक खर्च हो सकी है।

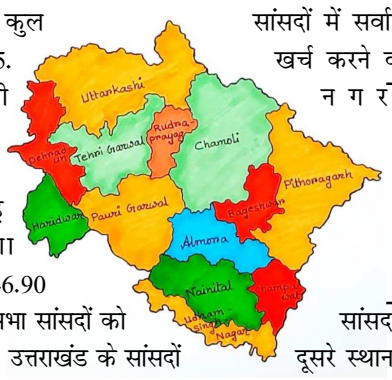

❑ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ खुलासा

नदीम को उपलब्ध सांसद वार विवरण के अनुसार नैनीताल उधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने दिसम्बर 25 तक अपने वर्तमान कार्यकाल में सांसद निधि से कुल 316 कार्य प्रस्तावित किये हैं जिसमें से 229 कार्य अधिकाारियोंद्वारा स्वीकृत किये गये है उसमें से 54 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 154 कार्य चल रहे हैं तथा 21 कार्य प्रारंभ नहीं हो सके है।

टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज लक्ष्मी शाह ने 128 कार्य प्रस्तावित किये हैं जिसमें से 89 कार्य अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, 11 कार्य पूर्ण हो चुके है, 64 चल रहे हैं तथा 14 कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं।

गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने वर्तमान लोकसभा सांसद कार्यकाल में कुल 4 कार्य प्रस्तावित किये हैं। अधि कारियों द्वारा 2 कार्य स्वीकृत किये हैं, 1 कार्य पूर्ण तथा 1 कार्य चल रहा दर्शाया गया है लेकिन दिसम्बर 2025 तक खर्च शून्य दर्शाया गया है।

अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा के स्वीकृत 4 कार्यों में से 2 कार्य प्रारंभ न होना तथा 2 कार्य चलना दर्शाया गया है तथा इस पर कुल निधि के 1 प्रतिशत से भी कम 0.041 करोड़ रू. खर्च होना दर्शाया गया है।

हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत के प्रस्तावित 16 कार्यों में से अधिकारियों ने 10 कार्य स्वीकृत किये है जिसमें मे 1 कार्य पूर्ण हुआ है 5 चल रहे है तथा 4 प्रारंभ नहीं हुये हैं। इस पर कुल निधि का 1 प्रतिशत से कम 0.080 करोड़ ध नराशि खर्च दर्शाया गया है।

राज्यसभा सांसदों में नरेश बंसल ने 191 कार्य प्रस्तावित किये है जिसमें से 144 कार्य अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं जिसमें 23 कार्य पूर्ण हुये है 92 चल रहे हैं तथा 29 दिसम्बर 2025 तक प्रारंभ नहीं हुये है। कल्पना सैनी द्वारा प्रस्तावित 121 कार्यों में से 89 कार्य अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं 26 पूर्ण हुये है 60 चल रहे है तथा 3 प्रारंभ नहीं हुये हैं। महेन्द्र भट्ट द्वारा अपने दिसम्बर 25 तक पूर्व कार्यकाल में 44 कार्य प्रस्तावित किये हैं 23 स्वीकृत हुये हैं, 2 कार्य पूर्ण हुये, 7 चल रहे है तथा 14 कार्य प्रारंभ नहीं हो सके है।

बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर ठगे 50 हजार व कानों के कुण्डल

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। मध्य हरिद्वार स्थित गोविंदपुरी के सामने मुख्य मार्ग पर एक बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर उनसे 50 हजार रुपये नगद और कानों के कुंडल ठगने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित का पकड़ने के लिए नाकेबंदी की, किन्तु आरोपित का कुछ पता नहीं चला। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित गोविंदपुरी के मान्यवर शोरूम से पहले जूस का ठेला लगता है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में राजीव नगर कॉलोनी निवासी बुजुर्ग महिला आनंदी पंजाब नेशनल बैक की शाखा से 50 हजार रुपये निकालकर लाई थी। घर जाते समय जब वह जूस वाले के सामने पहुंची तो उसे ठगों ने रोक लिया। बुजुर्ग महिला को अपने मोह जाल में फांसकर ठगों ने उससे 50 हजार रुपये और उसके कुंडल भी ठग लिए। कुछ देर बाद महिला को अपने ठगे जाने का अहसास हुआ। मामले की सूचना मिलते ही ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला आनंदी से पूरे प्रकरण की जानकारी ली। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ने के लिए चौकिंग अभियान चलाया है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही आरोपित को पकड़ लिया जाएगा।

गंगनहर में डूबे आईआईटी छात्र की तलाश जारी

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। गंगनहर में डूबे आईआईटी रुड़की के एमबीए द्वितीय वर्ष के छात्र आशीष शुक्ला की तलाश के लिए आज सुबह उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम, आर्मी और सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस के बुलावे पर मौके पर पहुंची टीमें सुबह से ही नहर में छात्र की तलाश में जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ टीम का नेतृत्व एसआई दीपक मेहता कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि घाट से लेकर आसफनगर झाल तक नहर में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है।

जानकारी के अनुसार आईआईटी का छात्र आशीष शुक्ला बीती शाम अपने दोस्तों के साथ नहर किनारे स्थित बाल्मीकि घाट पर बैठा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गंगनहर के तेज बहाव में बह गया। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आईआईटी के छात्र घाट पर पहुंच गए। साथ ही आईआईटी के सुरक्षा विभाग और फायर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन छात्र की तलाश के लिए तत्काल कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर छात्रों में नाराजगी देखी गई। अंधेरा होने के कारण सर्च अभियान शुरू नहीं हो सका था। हालांकि आज सुबह से एसडीआरएफ, आर्मी, गोताखोरों और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। फिलहाल छात्र का कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिससे परिजनों और साथियों में चिंता का माहौल बना हुआ है।

तहसीलदार विकास अवस्थी मौके पर सिंचाई विभाग के आलाधिकारियों से बात करते हुए और पानी कम कराने की बात कही जा रही है।

संयुक्त ट्रेड यूनियन्स संघर्ष समिति ने की देश व्यापी हड़ताल

संवाददाता

देहरादून। संयुक्त ट्रेड यूनियन्स संघर्ष समिति के आहवान पर देशव्यापी हडताल करते हुए सचिवालय का घेराव कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।

आज यहां संयुक्त ट्रेड यूनियन्स के आहवान पर सभी मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी देशव्यापी हडताल के दौरान गांधी पार्क में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने सचिवालय कूच किया। गांधी पार्क से वह राजपुर रोड, घंटाघर चौक से फिर राजपुर रोड, सुभाष रोड होते हुए सचिवालय पहुंचे जहां पर पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानूनों के स्थान पर लायी गयी चारों श्रम संहिताओं के साथ 12 घंटे काम करने के आदेश को रद्द किया जाये तथा श्रम कानूनों को ओर अधिक प्रभावशाली बनाया जाये। उन्होंने कहा कि मोटरयान अधिनियम 2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द करें व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 (1) एवं (2) को वापस लिया जाये। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 26 हजार रूपये मासिक घोषित किया जाये तथा न्यूनतम वेतन बोर्ड, उत्तराखण्ड कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड व ईएसआई की समितियों में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों सीटू, इंटक, एवं ऐटक के प्रतिनिधियों को रखा जाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एलिवेटेड रोड व एनजीटी के नाम पर बस्तियों को उजाडना बंद करो एलिवेटेड रोड योजना रदद की जाये। यदि किसी का भी घर ध्वस्त किया जाता है तो उसे पुनर्वास किया जाये। स्मार्ट मीटर लगाने के जनविरोध ी फैसले को वापस लिया जाये। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा रेहडी, पटरी, फुटपाथ व्यवसायियों व ई- रिक्शा कर्मकार का उत्पीडन पर रोक लगाओ तथा उन्हें मुख्य मार्गो से हटाना बंद कर वैन्डर घोषित किया जाये। इसके साथ ही बढे हुए न्यूनतम वेतन को सभी संस्थानों में लागू कर अक्टूबर व अप्रैल माह का महंगाई भत्ता जारी किया जाये।

❑सचिवालय का घेराव कर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।